शुगर सेक्टर पर कुछ कम हुआ सरकार का कंट्रोल

[पीटीआई *नई दिल्ली*]

सरकार ने रिफॉर्म्स के एक बड़े फैसले के तहत 80,000 करोड़ रुपए के शुगर सेक्टर को आंशिक रूप से कंट्रोल से मुक्त करने का फैसला किया। इससे मिलें ओपन मार्केट में चीनी बेच सकेंगी। सरकार ने राशन की दुकानों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलों के चीनी बेचने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी।

फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने कहा कि इस फैसले से रीटेल मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राशन की दुकानों के जरिए कम रेट पर चीनी बेचना जारी रखेगी। वह इसके लिए ओपन मार्केट से चीनी खरीदेगी। इस फैसले से सरकार पर शुगर सब्सिडी का सालाना बोझ दोगुना 5,300 करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि इंडस्ट्री हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकेगी।

सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए के शुगर सेक्टर को आंशिक रूप से डीकंट्रोल करने का फैसला किया

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने शुगर सेक्टर को आंशिक रूप से डीकंट्रोल करने का फैसला लिया। शुगर सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर था, जिस पर सरकार का कंट्रोल था। अभी मिलों को प्रोडक्शन का एक हिस्सा सरकार को प्रति किलो 20 रुपए की दर पर बेचना पड़ता है। गुरुवार के फैसले के बाद वे ओपन मार्केट में चीनी बेचने के लिए आजाद होंगी। सरकार मिलों से चीनी खरीदने के बाद उसे राशन की दुकानों से 13.50 रुपए प्रति किलो की दर से बेचती है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सीसीईए के फैसले के बाद राज्यों को ओपन मार्केट से चीनी खरीदनी पड़ेगी। केंद्र सरकार दो साल के लिए (सितंबर 2014 तक) राज्यों द्वारा खरीदी जाने वाली चीनी पर 32 रुपए प्रति किलो तक की सब्सिडी देगी।

थॉमस ने कहा कि सरकार की सब्सिडी 2,600 करोड़ रुपए से बढ़कर सालाना 5,300 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इस फैसले से चीनी की रीटेल कीमतें बढ़ जाएंगी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, 'चीनी मीठी थी, मीठी रहेगी।' सी रंगराजन ने फैसले को शुगर मिलों के लिए वाजिब इनसेंटिव बताया। रंगराजन की अगुवाई वाली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही सीसीईए ने शुगर को आंशिक रूप से कंट्रोल से मुक्त करने का फैसला लिया है।

The Economic Times (Hindi)
5/4/13